



पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से बात, मिडिल ईस्ट में शांति और होर्मुज की 'आजादी' पर दिया जोर

सीजफायर के बाद पहली बार पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम बातचीत हुई. फोन कॉल के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय हालात और हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी. (जीएनएस)।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान से टेलीफोन पर बातचीत की. बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और आगे की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी. प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में बनी समझ का स्वागत किया और कहा कि भारत लगातार यह मानता रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए.

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित

करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने समुद्री मार्गों पर आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता सुरक्षित बनाए रखने की अहमियत भी दोहराई. हालिया क्षेत्रीय संघर्ष के बावजूद ईरान के साथ भारत उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क और बहुपक्षीय मंचों के जरिए लगातार करीबी कूटनीतिक संवाद बनाए हुए है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान के बीच हुई बातचीत को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है. इस बीच, ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा था. अयातुल्ला खामेनेई की हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिका-इजरायल के हमले में मौत हो गई थी.

भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मागेरिटा अंतिम संस्कार समारोह में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. ईरानी अधिकारियों

के मुताबिक, सार्वजनिक श्रद्धांजलि समारोह 4 जुलाई को स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे तेहरान के इमाम खुमैनी ग्राँड प्रेयर ग्राउंड्स में शुरू होगा. इसी समय से आम लोगों के लिए भी स्थल खोल दिया जाएगा.



युद्ध के दौरान भी भारत ने ईरान से बनाए रखा संपर्क

पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता रहा, लेकिन भारत ने ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संपर्क बनाए रखे. उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, रणनीतिक बैठकों और मानवीय

सहयोग के जरिए नई दिल्ली ने तेहरान के साथ कई स्तरों पर बातचीत जारी रखी. संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान से दो बार बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात,



शांति, स्थिरता और संवाद की जरूरत पर चर्चा हुई.

विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची के लगातार संपर्क में रहे. संघर्ष के दौरान दोनों नेताओं के बीच पांच से अधिक बार बातचीत हुई. इन चर्चाओं में क्षेत्रीय हालात, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और तनाव कम

करने के प्रयासों पर फोकस रहा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इफ्कर विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत भी आए. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. ईरान के उप विदेश मंत्री डॉ. सईद खतिबजादेह भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे, जहां वह प्रमुख वक्ताओं में शामिल रहे.

इसके अलावा ईरान ने अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को भारत में आयोजित इफ्कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भेजा. इस दौरान ईरानी प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की. क्षेत्रीय संघर्ष के बावजूद ईरान ने भारत द्वारा आयोजित इफ्कर ऊर्जा मंत्रियों की बैठक समेत कई बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेना जारी रखा, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग की निरंतरता दिखाई दी.

केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की चली 4 घंटे मैराथन बैठक, जानें सभी विभागों के साथ क्या हुई चर्चा

पीएम मोदी और सचिवों की बैठक में ईज ऑफ़ ड्रूइंग बिजनेस और ईज ऑफ़ लिविंग के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं उस पर मंथन हुआ. (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक के साथ करीब 4 घंटे की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई, जिससे आम आदमी को फायदा मिले. ईज ऑफ़ ड्रूइंग बिजनेस और ईज ऑफ़ लिविंग के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभागों के साथ इसको लेकर भी मंथन हुआ. बेहतर तालमेल और सही फैसले लेने के लिए उन्होंने 'पीएम गतिशक्ति' (डट क्लर ३) प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया. पीएम मोदी ने सचिवों से कहा

कि सरकारी योजनाओं का असली मकसद सभी पूरा होगा, जब उनका सीधा और सकारात्मक असर आम



लोगों के जीवन पर दिखाई दे. पीएम मोदी ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जब देश ब्रिटिश सत्ता से आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा. बैठक में उन्होंने सचिवों को गवर्नेंस और इंफ़्लेमेटेशन पर ध्यान केंद्रित रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सरकारी कार्यों, खास तौर पर जन-केंद्रित पहलों में कोई ढिलाई या

देरी न हो. पीएम मोदी ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की थी. उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार की 'सुधार एक्सप्रेस' व्यवस्थागत बदलाव लेकर आई है और नागरिकों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाया है.

वरिष्ठ अधिकारियों ने संरचनात्मक सुधारों पर अपडेट दिया. यह समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे सहित कई मंत्रालयों में '52 साहब में 52 सुधार' जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसमें इन्हें लागू करने की समय-सीमा स्पष्ट रूप से तय की गई है. प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा तय समय-सीमा के भीतर परिणाम हासिल करने के महत्व पर जोर दिया है, जिससे समय-समय पर समीक्षा सरकार के कामकाज का एक अहम हिस्सा बन गई है.

यूरोप बना 'आग का गोला'! अस्पताल फुल-कब्रिस्तान भरे, क्यों धक्का उठा सूरज?-



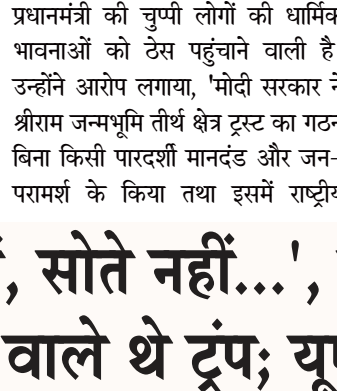
यूरोप इस समय अपने इतिहास की सबसे भयानक गर्मी का सामना कर रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कई देशों में हालात गंभीर हो गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर जा रहा है। आम लोगों की रोमरों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई जगहों पर बुनियादी सुविधाएं भी जवाब देने लगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख ट्रेड्स अदोनो ग्रेबेयेसस ने चेतावनी दी है कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने जवाब मांगते हुए पारदर्शिता की मांग की, जबकि अजय राय ने अयोध्या में हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया। राम मंदिर मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात: कांग्रेस (जीएनएस)।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर "सीधा आघात" है। पार्टी महासचिव

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय द्वारा 'एक्स' पर किए एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि श्रीराम मंदिर में कथित "लूट" पर प्रधानमंत्री की चुप्पी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया, 'मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड और जन-परामर्श के किया तथा इसमें राष्ट्रीय



स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को जगह दी। रमेश ने यह भी दावा किया कि बाद में पूरे ट्रस्ट को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर अपनी "चुप्पी तोड़ने" की मांग की। अजय प्रधानमंत्री की चुप्पी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया, 'मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड और जन-परामर्श के किया तथा इसमें राष्ट्रीय



यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (वरकडक) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी राजदूत ने यह वाक्या साझा किया। उन्होंने बताया कि कुछ हदों पर पहले मियामी में एक यूएफसी (UFC) फाइट इवेंट के दौरान वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैकस्टेज बैठे

थे। अचानक ट्रंप ने उनसे कहा कि चलो, प्रधानमंत्री मोदी की फोन लगाते हैं।

गोर ने बताया कि जब ट्रंप ने ऐसी इच्छा जताई तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि इस वक्त भारत में सुबह के 6 बजे रहे होंगे, तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह जाग रहे होंगे। वह बिल्कुल मेरी तरह हैं जल्दी उठने वाले। हालांकि, वह फोन कॉल अगले दिन की गई, लेकिन राजदूत ने कहा कि इस किस्से से पता चलता है कि किन नेताओं के बीच कितना दोस्ताना रिश्ता है। जब आप किसी के अच्छे दोस्त होते हैं, तो हर बात के लिए

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

राय ने दावा किया, 'उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जून को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन-पूजन के लिए जाने वाला था। मैं अयोध्या पहुंचा ही था कि भाजपा सरकार इतनी डर गई कि पुलिस मुझे होटल से गिरफ्तार कर अपनी जीप में बैठाकर ले जा रही है।' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन घोटालों और चढ़ावे की चोरी में शामिल लोगों को 'राम भक्तों के आने से डर' लग रहा है। उन्होंने भाजपा पर 'आस्था पर पहरा देने' का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई को 'कायरतापूर्ण' और 'निंदनीय' बताया। राय ने कहा, 'हम न रुकेंगे, न झुकेंगे।'

पहले से टाइम तय करने की जरूरत नहीं होती।

ट्रंप के दिल में भारत के लिए खास जगह राजदूत गोर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप आज भी भारत दौरे की यादों को बहुत पसंद करते हैं। उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुए 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे बड़े कार्यक्रमों ने दोनों देशों को बहुत करीब लाया था। ट्रंप अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी भारत आने की इच्छा रखते हैं। अगले 2 साल भारत-अमेरिका के लिए बेहद अहम अमेरिकी राजदूत के मुताबिक, दोनों देशों की सरकारों सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि काम पर भरोसा रखती हैं। आने वाले दो साल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत जरूरी हैं।



गरवी गुजरात हिन्दी



JioTV CHENNAL NO. 2002



Jio Air Fiber



Jio tv+



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv

Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



अयोध्या में बड़ा हादसा, बच्ची को बचाने उतरीं 5 महिलाएं सरयू में डूबीं, 3 की मौत, 2 लापता

अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में सरयू नदी में नहाने के



दौरान मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. नदी में डूब रही एक बच्ची को बचाने की कोशिश में पांच महिलाएं खुद गहरे पानी में समा गईं. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो की तलाश के लिए राहत

और बचाव अभियान लगातार जारी है. घटना के बाद सनाहा गांव में मातम पसरा है और जिलाधिकारी व एसएसपी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. (जीएनएस)।

अयोध्या: यूपी के अयोध्या से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. रौनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव में

नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. एक बच्ची को बचाने की कोशिश में पांच महिलाएं नदी में डूब गईं. इनमें से तीन महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि दो की तलाश अभी भी जारी है. प्रशासन और राहत-बचाव दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब नदी में नहाने के दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई. उसे बचाने के लिए महिलाएं एक-एक कर नदी में उतरीं, लेकिन तेज बहाव और गहराई की वजह से पांच महिलाएं डूब गईं.

ग्रामीणों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया और तीन महिलाओं को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. मृतकों की पहचान 55 वर्षीय सरजुल निशा, 40 वर्षीय नाजनीन और 19

वर्षीय मरियम के रूप में हुई है. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. दो अन्य महिलाओं की तलाश के लिए प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

मृतकों के परिजनों के मुताबिक सभी लोग घूमने और नहाने के लिए नदी पर गए थे. एक बच्ची के पानी में फिसलने के बाद उसे बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ. जिलाधिकारी अयोध्या ने बताया कि पांच लोग सरयू में डूबे हैं जिसमें से तीन बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच की है एक महिला के डूब रही थी जिसको बचाने के चक्कर में पांचो लोग डूबे हैं. जिसमें तीन लोगों के शव को रिकवर कर लिया गया दो की तलाश अभी भी जारी है.

लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की हत्या में तीन पर दोष सिद्ध, अब 7 जुलाई को सजा पर होगी सुनवाई

(जीएनएस)। लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को दोषसिद्ध करते हुए जेल भेज दिया है। सजा के बिंदु पर सात जुलाई को सुनवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इंद्रदेव की पुत्री लक्ष्मी सिंह इस समय नोएडा की पुलिस आयुक्त और दामाद राजेश्वर सिंह लखनऊ सरोजनीनगर सीट से भाजपा विधायक हैं।

सीबीआई मामले के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा के समक्ष सीबीआई के अभियोजन अधिकारी केपी सिंह व वादी के विशेष अधिवक्ता

आरके यादव ने बताया कि आठ अगस्त 2002 को शाम चार बजे कैसरबाग टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे पूर्व मंत्री बक्शी दीदी के घर के निकट अधिवक्ता इंद्रदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी।

दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा मामले में उनकी पत्नी पीसीएस अधिकारी नयनतारा सिंह ने थाना कैसरबाग में रामकुमार वर्मा, सुरेश वर्मा, सुरजन वर्मा, सुरेश वर्मा उर्फ डाक्टर, सुषमा वर्मा के खिलाफ हत्या



का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच कर रही सीबीआई की विवेचना में आरोपित मन्नालाल गुप्ता, वेद प्रकाश उर्फ नेता, विक्रम यादव कालिया, छोटेलाल और छोटे, वृजेश यादव उर्फ मुन्ना एवं पन्ना सिंह के नाम प्रकाश में आए, जिनमें विक्रम

यादव उर्फ कालिया ने स्कूटर पर लिफ्ट लेने के बाद इंद्रदेव सिंह की कनपटी पर 12 बोर के तमंचे से गोली मार दी थी। सीबीआई ने 2004 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

वर्ष 2004 में ही अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए गए थे न्यायालय के समक्ष चली लंबी लड़ाई के उपरांत न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों विक्रम यादव उर्फ कालिया, पन्ना सिंह और वृजेश यादव उर्फ मुन्ना को धारा 302 सपठित धारा 120 बी आईपीसी के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया है। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान शेष तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो गई।

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अब बंथरा जाना होगा:लखनऊ का पहला डीएल और टेस्टिंग सेंटर शुरू, डीटीटीआई करेगी स्थायी लाइसेंस का टेस्ट

(जीएनएस)। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लखनऊ के आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए बंथरा स्थित नए ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग सेंटर जाना होगा। मंगलवार से शुरू हो रहे इस सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह करेंगे।

परिवहन विभाग ने स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट कराने की जिम्मेदारी ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (डीटीटीआई) को सौंप दी है। अब आवेदकों का टेस्ट आधुनिक ट्रैक पर तय मानकों के अनुसार कराया जाएगा। टेस्ट में सफल होने के बाद ही स्थायी ड्राइविंग



लाइसेंस जारी किया जाएगा। एआरटीओ ने दी जानकारी एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप

कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार से ड्राइविंग टेस्ट के लिए सभी आवेदकों को बंथरा स्थित सेंटर पर पहुंचना

होगा। विभाग ने इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाना है।

लखनऊ में चार सेंटर बनाने की योजना

परिवहन विभाग की योजना लखनऊ में कुल चार ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने की है। फिलहाल बंथरा में पहला सेंटर शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे सेंटर खोले जाएंगे, ताकि आवेदकों को सुविधा मिल सके और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सके।

रिजल्ट री-वैल्यूएशन की टेंशन खत्म! बिना नए मार्क्सशीट के भी ऊ्र में ऐसे पक्का करें अपना रजिस्ट्रेशन

(जीएनएस)। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देशभर के लाखों छात्र इस समय अपने पर्सदीदा कॉलेज और कोर्स में दाखिला पाने की तैयारी कर रहे हैं। इस साल भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश का आधार उवएछ (UG) 2026 का स्कोर होगा और सभी उम्मीदवारों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) 2026 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

इसी बीच CBSE कक्षा 12 के उन छात्रों के लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का री-वैल्यूएशन कराया था, लेकिन अभी तक उनका संशोधित परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे कई छात्र इस बात को लेकर परेशान थे कि बिना नए रिजल्ट के क्या वे एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे या नहीं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे री-वैल्यूएशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर

सकेगे। री-वैल्यूएशन रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र क्या करें? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि जिन छात्रों ने उइएर कक्षा 12 के



रिजल्ट का री-वैल्यूएशन कराया है और अभी तक संशोधित रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उन्हें आवेदन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे छात्र उरअर 2026 पोर्टल पर फिलहाल अपने पुराने यानी री-वैल्यूएशन से पहले वाले बोर्ड अंक दर्ज करके आवेदन पूरा कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी का कहना है कि आवेदन के समय पुराने अंक भरने से किसी भी छात्र का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। इससे छात्र समय पर एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेगे और बाद में जरूरत पड़ने पर अपने अंक

अपडेट भी कर पाएंगे। संशोधित रिजल्ट आने के बाद बदल सकेगे नंबर

उब ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही उइएर की ओर से री-

छात्रों का री-वैल्यूएशन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि उरअर पोर्टल कई सप्ताह तक खुला रहेगा, इसलिए उम्मीदवारों के पास अपने बोर्ड के संशोधित अंक अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी पूरी प्रक्रिया को इस तरह चला रही है ताकि किसी भी छात्र को केवल री-वैल्यूएशन की वजह से नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए सभी उम्मीदवार तय समय के भीतर आवेदन जरूर करें।

एडमिशन में सबसे अहम होगा CUET (UG) 2026 स्कोर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सभी अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला केवल CUET (UG) 2026 के स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उवएछ के अंकों की होगी। कक्षा 12 के बोर्ड अंकों का उपयोग मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उम्मीदवार ने आवश्यक योग्यता पूरी की है और वह संबंधित कोर्स के लिए पात्र है।

लखनऊ में 122 होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन का निरीक्षण, बेसमेंट में चल रहीं अवैध गतिविधियों पर होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा



की. (जीएनएस)।

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिये.

बैठक में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अवागत कराया कि ज्वाइंट सर्वे में विभिन्न जोन में कुल 122 होटल, गेस्ट

होटल प्रबंधन को लीज पर आवंटित की गयी ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण पाया गया.

इसी तरह एक होटल में बेसमेंट पार्किंग में बेकरी, स्टॉफ रूम व लॉन्ड्री संचालित मिली. इस क्रम में एक होटल में भी कुछ गड़बड़ी पायी गयी. इसके अलावा आशियाना में स्थित एक होटल में बेसमेंट में अवैध रूप से बैन्क्वेट हॉल संचालित पाया गया. वहीं, विभूतिखंड स्थित एक नामचीन होटल में बेसमेंट में पार्किंग की जगह बैन्क्वेट हॉल समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की बात सामने आयी.

मंडलायुक्त ने रिपोर्ट देखने के बाद ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों में अवैध गतिविधियां मिली हैं, उन्हें तत्काल रोका जाए. अगर निर्धारित समय-सीमा के अंदर सम्बंधित भवन मालिक/प्रबंधक नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया जाए.

मंडलायुक्त ने यह भी निर्देशित

सेवारत शिक्षकों को परीक्षा के दिन मिलेगा विशेष अवकाश, लखनऊ में 46 केंद्रों पर 96,454 अभ्यर्थी होंगे शामिल

(जीएनएस)। लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (वडवएछ-2026) 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. मंगलवार को लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों, सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की.

वहीं वडवएछ-2026 में सम्मिलित होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु 2, 3 एवं 4 जुलाई को विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है.

डीएम ने बताया, लखनऊ में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 2 एवं 3 जुलाई को परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा सेकेंड पाली दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 4 जुलाई 2026 को परीक्षा केवल प्रथम पाली (प्रातः 09:30 बजे से 12:00 बजे तक) में आयोजित होगी. डीएम ने कहा, परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार की वीडियोग्राफी कराते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया, 2 जुलाई की प्रथम पाली में 19,734 एवं द्वितीय पाली में 19,734, 3 जुलाई को प्रथम पाली में 19,734 और द्वितीय पाली में 19,734 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे.

4 जुलाई को प्रथम पाली में 17,518 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित

होंगे. जनपद में कुल 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा के सफल संचालन हेतु जनपद में 46 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 46 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.

डीएम ने बताया, रेलवे स्टेशन एवं

उन्होंने जलकल को आवश्यकतानुसार पानी के टैंकर तथा नगर निगम को मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही परिवहन विभाग एवं रेलवे को परीक्षार्थियों की संभावित



बस स्टेशन पर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे. इन हेल्पडेस्क पर परीक्षा से संबंधित जानकारी, परीक्षा केंद्रों की जियो-टैग लोकेशन तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रवेश पत्र प्रदर्शित करने पर उन्हें परीक्षा केंद्र की जियो-टैग लोकेशन सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. हेल्पडेस्क पर सिविल डिफेंस के वार्डनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जुलाई शाम तक सभी हेल्पडेस्क क्रियाशील कर दिए जाएं.

जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग एवं रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशनों एवं बस स्टेशनों पर स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित कर ली जाए. विशेष रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन एवं प्रमुख बस अड्डों पर रैनु बसेरा/होलिडिंग एरिया की सुनचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जहां परीक्षार्थियों के लिए पेयजल एवं शौचालय की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहे.

संख्या को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बसों एवं ट्रेनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए.

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री सुरक्षित रखने हेतु कर्ताक रूप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, केलकुलेटर, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, पर्स, बेल्ट, गॉगल्स, अड्डों पर स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित कर ली जाए. विशेष रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन एवं प्रमुख बस अड्डों पर रैनु बसेरा/होलिडिंग एरिया की सुनचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जहां परीक्षार्थियों के लिए पेयजल एवं शौचालय की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहे.

जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों का प्रवेश, बायोमेट्रिक सत्यापन, तलाशी, गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल एवं अन्य मूलभूत

किया कि जिन प्रतिष्ठानों में स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण सम्बंधी खामियां उजागर हुई हैं. उन प्रतिष्ठानों को पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाए.

मंडलायुक्त ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये कि होटल, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर क्लासेस, होस्पिटल/नर्सिंग होम, जिम समेत ऐसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जाए, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है. इसमें बेसमेंट में संचालित प्रतिष्ठानों की विशेष रूप से जांच की जाए. उन्होंने कहा कि सभी भवनों में सुरक्षा के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए.

इस मौके पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव अतुल कुमार व मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह समेत समस्त जोनल अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी निर्धारित मानकों एवं समय-सारिणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परीक्षा सामग्री को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाए तथा प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए. साथ ही परीक्षा से एक दिन पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों, विशेषकर शौचालयों सहित पूरे परिसर की सघन जांच कराने के निर्देश दिए.

प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सदीप सिंह ने बताया, वडवएछ-2026 में बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक भी प्रतिभाग करेंगे. शिक्षकों को बिना किसी प्रशासनिक या कार्यगत बाधा के परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष अवकाश स्वीकृत किया है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के ज्ञान, दक्षता और पेशेवर क्षमता को निरंतर सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. वडवएछ जैसी परीक्षाएं शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का अवसर प्रदान करती हैं. इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी शिक्षक को अवकाश संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े.

यूपी: 'जो चढ़ावा चुरा सकते हैं, वे वोट और सांसद क्यों नहीं', अखिलेश यादव के हमले पर सीएम योगी का पलटवार

(जीएनएस)। प्रयागराज , प्रयागराज में प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, वे वोट और सांसद भी चोरी क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी को सावधान रहना होगा।

सिविल लाइंस स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा को अब न तो चंदा मिलेगा, न ही दान। वोट भी अब कोई नहीं देगा। इसी कारण भाजपाईं घबराए हैं। उन्होंने सच्चे सनातनियों से अपील की कि वे न जो भाजपा से टिकट मांगें और न ही वोट दें।

अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा और दान चोरी आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसके साथ खिलवाड़ किया गया है। मामले की जांच चल रही है।

योजनाएं बजट साफ करने के लिए बनाई जाती हैं। प्रयागराज में मेले पर 80 से 90 करोड़ रुपये खर्च हुए पर त्रिवेणी में बदलाव नहीं आया। उन्होंने

मां गंगा की सफाई के वादे पर भी प्रश्न उठाए। अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी गंगा का पानी साफ नहीं हुआ है। भाजपा के

कार्यकाल में नदियां नहीं, अरबों का बजट साफ हुआ। सपा प्रमुख ने कसा तंज कहा- एक मंत्री आधे साफ, चुनाव में पूरी तरह हो जाएंगे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं, उन्होंने कहा कि प्रयागराज के एक मंत्री अभी तो वे

आधे साफ हुए हैं, चुनाव में पूरी तरह हो जाएंगे। सपा प्रमुख ने प्रेसवार्ता के दौरान अच्छी सीख के महत्व पर जोर दिया। कहा कि अच्छी सीख इन्सान को बेहतर बनाती है। यह जिंदगी जीने का सही सबक सिखाती है।

सीएम योगी और अखिलेश के बीच वार-पलटवार आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर मथुरा-वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बोलना चाहिए। तुष्टिकरण से उबरना चाहिए। तभी जनता उनके बचले हुए रूख पर विश्वास करेगी। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में पलटवार किया कि अयोध्या में चंदा चोरी करने के बाद क्या अब मथुरा में "माखन" चुराने का प्लान है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 77 देशों से आए 3421 रिकॉर्ड आवेदन, जर्मनी और पोलैंड के छात्रों ने भी दिखाई रुचि

सत्र 2025-26 में 2083 आवेदन आए थे. विश्वविद्यालय ने मात्र एक वर्ष में 64 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है. लखनऊ विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड आवेदन आए. (जीएनएस)।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा, निवेश और नवाचार के साथ-साथ अब वैश्विक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहचान स्थापित कर रहा है. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, विश्वविद्यालयों के आधुनिकीकरण, सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की नीतियों का सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है.

इसका सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ विश्वविद्यालय है, जहां शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 77 देशों से रिकॉर्ड 3421 अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है. यह संख्या पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के 2083 आवेदनों की तुलना में 1338 अधिक है. विश्वविद्यालय ने मात्र एक वर्ष में 64 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है. यह उपलब्धि दशरती है कि उत्तर प्रदेश अब केवल देश के छात्रों का ही नहीं, बल्कि दुनिया के विद्यार्थियों का

अमेरिका-इटली रिश्तों में दरार? ट्रंप पर फिर भड़कीं मेलोनी, अब क्या बोलेंगे?

(जीएनएस)। अमेरिका और इटली के रिश्तों में एक नया विवाद सामने आया है। इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि मेलोनी ने ऋषि शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कई बार रिव्क्स्ट की थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इटली में मेलोनी की पॉपुलरटी कम हो रही है और वह अमेरिका के साथ दोस्ती दिखाकर अपनी छवि सुधारना चाहती हैं। वहीं मेलोनी ने अब एक इंटरव्यू में अब ट्रंप और अमेरिका को लेकर कई तीखी टिप्पणियां की हैं।

मेलोनी ने दिया सीधा जवाब

एक इतालवी मीडिया इंटरव्यू में जोर्जिया मेलोनी ने साफ कहा कि उनकी सरकार अमेरिका विरोधी नहीं है, लेकिन इटली के सम्मान और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह कभी किसी विदेशी नेता के सामने नहीं झुकी हैं और न ही भविष्य में झुकेंगी। उनके मुताबिक, मजबूत अंतरराष्ट्रीय रिश्ते बराबरी, सम्मान और साफ बातचीत पर टिके होते हैं, न कि व्यक्तिगत दावों या सोशल मीडिया पोस्ट पर।

पुरानी कार,बाइक का अब क्या होगा ? पेट्रोल-डीजल गाड़ियां बंद होंगी ? दिल्ली ईवी पालिसी के फायदे-नुकसान समझ लीजिए

(जीएनएस)। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV Policy 2.0) लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे मंजूरी देते हुए साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक दिल्ली चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। सरकार का टारगेट साफ है कि दिल्ली में होने वाले नए रजिस्ट्रेशन में 95% गाड़ियां सिर्फ इलेक्ट्रिक हों।

इस बड़े फैसले के बाद हर दिल्लीवाले के मन में यही सवाल है कि उनके पास जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी (CNG) गाड़ी है, उसका क्या होगा ? यानी पहले से जो कार, बाइक या ऑटो-बस, ट्रक है, उसका क्या होगा ? क्या सरकार उसे सड़क पर चलने से रोक देगी ? आइए नई एए पॉलिसी के नफे-नुकसान और अपनी गाड़ी पर पड़ने वाले असर को बारीकी से समझते हैं।

पुरानी गाड़ियों का क्या होगा ? पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी ?

सबसे पहले अपने दिल से यह डर निकाल दीजिए कि आपकी मौजूदा गाड़ी तुरंत कबाड़ हो जाएगी। अगर आपके पास पहले से कोई चालू हालत में बाइक, स्कूटर, कार या ऑटो है, तो

भी भरोसेमंद शैक्षणिक गंतव्य बनता जा रहा है.

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस साल 77 देशों के विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में



प्रवेश के लिए आवेदन किया है. इनमें बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, सूडान और तंजानिया से सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त जर्मनी और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों से भी आवेदन प्राप्त होना विश्वविद्यालय की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण माना जा रहा है.

पाठ्यक्रमवार आंकड़ों पर नजर डालें तो स्नातक कार्यक्रमों के लिए सर्वाधिक 2552 आवेदन प्राप्त हुए हैं. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 595 छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि विभिन्न विषयों में पीएचडी के लिए 274 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. शोध एवं नवाचार

के क्षेत्र में बढ़ती रुचि विश्वविद्यालय की अकादमिक गुणवत्ता और अनुसंधान क्षमता को भी रेखांकित करती है.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय



ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, स्मार्ट कैंपस, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम, शोध संस्कृति को प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की वैश्विक छवि को मजबूत किया है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में विदेशी छात्र अब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं.

इस समय उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्रेडिंग प्राप्त हो रही है जो

उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हव बना रही है. लखनऊ और नोएडा में अन्य प्रदेशों, देश विदेश के छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं जहां पहले उत्तर प्रदेश के छात्र बाहर पढ़ने जाया करते थे. लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आवेदनों में हुई यह अभूतपूर्व वृद्धि विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों और छात्र-अनुकूल वातावरण का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित बहुविषयक पाठ्यक्रम, वैश्विक अनुसंधान के अवसर तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दुनिया भर में सराहना मिल रही है.

विश्वविद्यालय अपने सभी विदेशी विद्यार्थियों को सुरक्षित, समावेशी, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ ने प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी है. सभी आवेदनों का दस्तावेज सत्यापन, पात्रता परीक्षण तथा वीजा संबंधी औपचारिकताओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा, ताकि विदेशी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

रिश्तों की झलक

राजनीतिक विशेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के बदलते रिश्तों की भी झलक दिखाता है। जोर्जिया मेलोनी खुद को एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश करती रही हैं। ऐसे में ट्रंप की व्यक्तिगत टिप्पणी को उन्होंने इटली के सम्मान से जोड़कर देखा और उसी अंदाज में जवाब दिया।

NATO और G7 पर भी पड़ सकता है असर

फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के बाद बड़े इस विवाद ने NATO के सहयोगी देशों का भी ध्यान खींचा है। कई यूरोपीय देश यह देख रहे हैं कि आगे इटली क्या कदम उठाता है। रक्षा खर्च, सुरक्षा समझौतों और अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच मेलोनी का यह रुख दूसरे यूरोपीय देशों को भी अपनी संप्रभुता पर ज्यादा जोर देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

इटली की राजनीति में भी

छिड़ी बहस

इस पूरे विवाद का असर इटली की घरेलू राजनीति पर भी दिख रहा है। मेलोनी के समर्थक उनके सख्त रुख की तारीफ कर रहे हैं और इसे देश के सम्मान की रक्षा बता रहे हैं।

इसी वजह से 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल या सीएनजी मोटरसाइकिल और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अगर

गाड़ियों पर क्या असर? नई पॉलिसी में छोटे कमर्शियल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर दिया गया है। खासकर टा कैटेगरी के लाइट कमर्शियल व्हीकल, जिनका कुल वजन 3500 किलोग्राम तक होता है, उन्हें इलेक्ट्रिक अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार पहले साल ऐसे इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1 लाख तक का खरीद इसेंटिव देगी। इतना ही नहीं, दिल्ली में रजिस्टर्ड पहले 1000 इलेक्ट्रिक मीडियम ट्रकों को 10 साल तक "नो एंट्री" समय में भी राहत देने की घोषणा की गई है। इससे लॉजिस्टिक्स कंपनियों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की लागत कम हो सकती है।

स्कूल बसों के लिए भी तय हुई टाइमलाइन नई पॉलिसी केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है। दिल्ली के स्कूलों को भी अगले कुछ वर्षों में अपने बस बेड़े का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक करना होगा।

पॉलिसी लागू होने के दो साल के भीतर कम से कम 10 प्रतिशत स्कूल बसें इलेक्ट्रिक करनी होंगी। तीन साल के बाद लक्ष्य 20 प्रतिशत और 31 मार्च 2030 तक 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इसमें स्कूल की अपनी बसें और किराए पर ली गई बसें दोनों शामिल होंगी।

लखनऊ एयरपोर्ट को मिला देश का पहला 'ईट राइट' टैग, बेहतर खाने के लिए श्री स्टार रेटिंग भी

(जीएनएस)। लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 'ईट राइट कैंपस' का सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। फूड सेफ्टी और हाइजीन के ऊंचे मानकों को पूरा करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से यह प्रमाण पत्र मिला है। यह सर्टिफिकेट 24 मार्च, 2026 से 23 मार्च, 2028 तक मान्य है। इसके तहत ऋरअक की गाइडलाइंस के अनुसार श्री-स्टार कंप्लायंस रेटिंग दी गई है। यह सर्टिफिकेट औपचारिक रूप से लखनऊ ईस्ट के एडिशनल

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह ने सौंपा। यह मान्यता एयरपोर्ट

मिली है। इन नियमों का हुआ आकलन



परिसर में चल रहे फूड आउटलेट्स और फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के विद्यार्थियों को सुरक्षित

ऑडिट में चार क्षेत्रों में नियमों के पालन का आकलन किया गया: सुरक्षित भोजन, स्वस्थ भोजन,

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो हादसों में पांच घायल, टायर फटना और नींद की झपकी बनी वजह

(जीएनएस)।

फतेहाबाद (आगरा)। आगरा-

लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात और मंगलवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। दोनों घटनाओं में यूपीडा की टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य कराया।

पहली घटना सोमवार देर रात करीब 3:40 बजे किलोमीटर 33 300 (आरएचएस) पर हुई। देवरिया से गुरुग्राम जा रही कार का अचानक टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार



चालक मधुसूदन सुरक्षित रहे, जबकि कार में सवार रवि प्रकाश, कुसुमलता और राजाराम घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर प सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा

शुभेंदु अधिकारी के गाजा पर बयान से मचा बांग्लादेश में बवाल, संसद में उठा मुद्दा, क्या है पूरा मामला?

(जीएनएस)।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव देखने को मिल रहा है। इस बार मामला बांग्लादेश की संसद तक पहुंच गया है। नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के सांसद और मुख्य विपक्षी सचेतक नाहिद इस्लाम ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बयानों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अंतरिम सरकार से कहा कि इस मुद्दे पर भारत के सामने सख्त राजनयिक विरोध दर्ज कराया जाए। नाहिद का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा आपसी सम्मान पर आधारित रहे हैं और ऐसे बयान दोनों देशों के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

शुभेंदु अधिकारी के बयान पर क्यों मचा विवाद?

संसद में बोलते हुए नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की संप्रभुता और उसके इतिहास को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उनके मुताबिक, भारतीय नेता ने कथित तौर पर कहा था कि बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की वजह से है। नाहिद ने इस बयान को बांग्लादेश के आत्मसम्मान के खिलाफ बताया और कहा कि विदेश मंत्रालय को इस पर तुरंत जवाब देना

चाहिए। संसद में मौजूद कई विपक्षी सांसदों ने भी उनके बयान का समर्थन किया।

'गाजा जैसा सबक' वाले बयान पर भी नाराजगी

नाहिद इस्लाम ने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी चुनवा से पहले और बाद में लगातार बांग्लादेश को लेकर बयान देते रहे हैं। उनके मुताबिक, एक चुनावी सभा में शुभेंदु अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि भारत जब चाहे बांग्लादेश में मौजूद अवैध घुसपैठियों को वापस भेज सकता है। इसके अलावा, नाहिद ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय नेता ने गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को "सबक सिखाने" की बात कही थी। उन्होंने इसे एक संप्रभु देश के लिए बेहद आपत्तिजनक बताया और भारत सरकार के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराने की मांग की।

नई राजनीतिक स्थिति से बदले समीकरण यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने

'पापा बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे', आखिरी कॉल और स्नेहा की ससुराल में दर्दनाक मौत! 3 साल की लव मैरिज का अंत

(जीएनएस)।

'पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे...' ये आखिरी शब्द थे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी 20 वर्षीय स्नेहा के। 27 जून की रात पिता को फोन करने के कुछ देर बाद ससुराल में ही उसकी मौत हो गई। जिस लड़की ने परिवार के विरोध के बावजूद अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया था, उसकी जिंदगी का अंत तीन साल में हो गया। पुलिस ने पति आकाश खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी ससुराल वाले फरार। लव मैरिज का खौफनाक अंत सभी के रोंगटे खड़े करने वाला साबित हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे क्या हुआ...

पिता से लगाई थी मदद की गुहार यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे का है। 27 जून की रात स्नेहा ने अपने पिता दीपक कुमार को

फोन किया। बातचीत के दौरान वह बेहद डरी हुई थी और रोते हुए मदद मांग रही थी। पिता के अनुसार, उसने कहा कि सासुराल वाले उसे मार डालेंगे और तुरंत आने की गुहार लगाईं।

पिता उस समय काम के सिलसिले में बाहर थे। उन्होंने बेटी को समझाया कि अगर, खतरा महसूस हो रहा है तो वह अपनी मां के पास चली जाए। लेकिन यह पिता-बेटी की आखिरी बातचीत साबित हुई। कुछ देर बाद सूचना मिली कि स्नेहा की मौत हो गई।

20 साल की स्नेहा का पड़ोस में रहने वाले आकाश खटीक (24) से

प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शुरूआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। बताया गया कि वर्ष 2024 में दोनों घर छोड़कर चले गए। लगभग एक महीने तक घर से दूर रहने के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए और सामाजिक रूप से विवाह करा दिया गया। शादी के बाद स्नेहा का मायका दिल्ली शिफ्ट हो गया, जबकि आकाश बुढ़ाना में ही एक वाटर पार्क में मैनेजर के रूप में काम करने लगा।

'दहेज नहीं मिला, इसलिए ताने शुरू हो गए'

स्नेहा के पिता का आरोप है कि प्रेम विवाह के कारण दहेज नहीं मिला,

सस्टेनेबल भोजन और जागरूकता बढ़ाना। इस ऑडिट में एयरपोर्ट परिसर के सभी फूड आउटलेट्स और खाद्य सेवा प्रदाताओं का विस्तृत मूल् यांकन किया गया। इसके अलावा यात्रियों और फूड हैंडलर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का भी मूल्यांकन किया गया।

दो साल के लिए वैध रहेगा प्रमाण पत्र

इस प्रमाण पत्र के साथ एयरपोर्ट की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के उत्कृष्ट अनुपालन के लिए 3 स्टार रेटिंग दी गई है। FSSAI की तरफ से यह प्रमाणपत्र 24 मार्च 2026 से 23 मार्च 2028 तक दो सालों के लिए वैध रहेगा।

दूसरी घटना मंगलवार को किलोमीटर 8 900 (एलएचएस) पर हुई। आगरा से फिरोजाबाद जा रहे बाइक चालक विशाल को रास्ते में नींद की झपकी आ गई, जिससे बाइक दाहिनी ओर लगे एमसीवी बैरियर से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार रोहिणी और मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि चालक विशाल को चोट नहीं आई।

सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी सुधीश कुमार शुक्ला और लुहारी चौकी प्रभारी देवेन्द्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घायलों को निजी एंबुलेंस से सर्वोदय हॉस्पिटल, आगरा भेजा गया।

सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी सुधीश कुमार शुक्ला तथा नदौता चौकी प्रभारी अनुज कुमार नागर मौके पर पहुंचे। घायलों को निजी एंबुलेंस से सर्वोदय हॉस्पिटल, आगरा भेजा गया।

को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को नुकसान पहुंचा।

भारतीय उच्चायुक्त और हिंसा पर लगाए आरोप

नाहिद इस्लाम ने ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त को लेकर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि नए राजनयिक को अपने कार्यकाल की शुरूआत पुरानी नीतियों पर खेद जताकर करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के कुछ जिम्मेदार लोग भारत में शरण लिए हुए हैं। नाहिद का दावा है कि अवामी लीग से जुड़े कुछ लोग भारत में बैठकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं।

भारत ने इस मामले पर क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों को बयानबाजी से बचते हुए बातचीत और आपसी सम्मान के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। यही दोनों देशों के रिश्तों और क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

